



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं ९४]
No. 94]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल १०, २०१२/चैत्र २१, १९३४

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2012/CHAITRA 21, 1934

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, १० अप्रैल, २०१२

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन.गण. के मूल के या वहाँ से निर्यातित भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए छनने वाले फ्रेंट एक्सल बीम और स्टेयरिंग नकलें के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच संबंधी निर्णयोपरांत मौखिक सुनवाई—अंतिम जांच परिणाम ।

आदेश सं. १४/१९/२००८-डी जी ए डी.—माननीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट) के दिनांक ११ अगस्त, २०११ के अंतिम आदेश सं. एडी/३१-५१/२०११-ए डी के अनुपालन में ऊपर उल्लिखित विषय पर २३ जनवरी, २०११ को एक निर्णयोपरांत सुनवाई की गई थी जिसमें वर्तमान जांच में भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लेने हेतु अनुरोध किया था ।

२ उक्त सुनवाई के समापन पर मौखिक रूप से अनुरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने उनके अनुरोधों को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर लिखित में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था । उनसे तत्पश्चात खंडन भी प्रस्तुत करने को कहा गया था ।

३ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों और तत्संबंधी खंडनों पर संगत समझी गई सीमा तक इस आदेश में विधिवत रूप से विचार किया गया है । हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार जांच की गई है :-

मै. हुबेर्ड ट्री-रिंग ऑटो एक्सल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.; मै. हुबेर्ड ट्री-रिंग फोर्जिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.; मै. हुबेर्ड ट्री-रिंग मोटर स्टेयरिंग गियर कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.; मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड, भारत और मै. अशोक लेयलेड लिमिटेड, भारत की ओर से किए गए लिखित अनुरोध :

४. इन हितबद्ध पक्षकारों की ओर से संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

हुबई ग्रुप द्वारा उनके लिए विशिष्ट मुद्रों से संबंधित अनुरोध

क.1 सुनवाई में भागीदारी अनुरोध करने पर की गई थी और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एस एल पी पर कोई विचार किए बिना है ।

क.2 बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार नहीं देना निम्नलिखित कारणों से अनुचित है :-

(i) सरकार द्वारा केवल शेयरधारिता के कारण बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं के अंतर्गत नियंत्रक को अपात्र नहीं ठहराया जा सकता है - जेझियांग जियान कैमिकल इंडस्ट्रियल ग्रुप कंपनी लिमिटेड बनाम काउंसिल फॉर यूरोपियन यूनियन मामले में यूरोपीय समुदाय के प्रथम मामला न्यायालय (चौथा चैम्बर) (17 जून, 2009) ।

(ii) प्राधिकारी ने अन्य के साथ चीन जन.गण. को स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में एक चीनी उत्पादक लिस्को को और बाल बियेरिंग मामले में चीनी नियंत्रकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया है । प्राधिकारी का पूर्ववर्ती निर्णय 'यह दर्शाता है कि चीन जन.गण. में इरपात की कीमतें उनके वास्तविक बाजार मूल्य को दर्शाती हैं ।

क.3 चीन की सरकार द्वारा प्रदत्त कथित सब्सिडीयों के कारण हुई कथित क्षति के उपचार के रूप में पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता है ।

क.4 सामान्य मूल्य के निर्धारण को गोपनीय नहीं रखा जा सकता है - प्रमुख निविष्टियों के नाम और उनकी कीमतें गोपनीय नहीं समझी जा सकती हैं ।

ख. टाटा मोटर्स द्वारा किए गए अनुरोध

ख.1 याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग नहीं है क्योंकि कुल उत्पादन में उसका हिस्सा टाटा मोटर्स के 64.23% के हिस्से के मुकाब्ले केवल 28.17% है ।

ख.2 यह याचिका नियम 5(3) (ख) के स्पष्टीकरण के अंतर्गत यथापेक्षित घरेलू उद्योग द्वारा नहीं की गई थी ।

ख.3 टाटा मोटर्स/एच वी ए एल वस्तुतः घरेलू उत्पादक है- प्राधिकारी टाटा मोटर्स/एच वी ए एल को उत्पादकों के रूप में मानने से इंकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि

(i) एच वी ए एल और टाटा मोटर्स दो अलग-अलग विधिक सत्ताएं हैं । दो अलग-अलग विधिक सत्ताओं के बीच आबद्ध खपत नहीं हो सकती है ।

(ii) किसी एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी के संपूर्ण उत्पाद की केवल खरीद कर लेने को आबद्ध खपत नहीं कहा जा सकता है । एच वी ए एल एफ ए बी और एस के की आपूर्ति किसी भी वाहन विनिर्माता को कर सकता है यदि उपयुक्त आदेश प्राप्त हों ।

(iii) टाटा मोटर्स/एच वी ए एल की खरीद को अलग-अलग बाजार के रूप में मानना पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के प्रावधानों के बिल्कुल विरुद्ध है क्योंकि

उसमें उल्लिखित पृथक बाजार माने जाने के लिए उल्लिखित दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई है ।

(iv) पिंग आयरन विनिर्माता एसोसिएशन मामले में सेस्टेट के निर्णय को वर्तमान मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस मामले में एक ही पक्षकार ने उत्पाद की आबद्ध खपत की थी । वर्तमान मामले में एफ ए बी और एस के का उत्पाद एच वी ए एल द्वारा हुआ है और उसे टाटा मोटर्स को बेचा गया था । यू एस : कॉटन यार्न (डी एस 192 आर) मामले में डब्ल्यू टी ओ के पैनल के निर्णय को माना जाए ।

ख.4 याचिकाकर्ता चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के एक निर्यातक से संबंधित है-जैसा कि अंतिम जांच परिणाम के पैरा 17.2 में प्राधिकारी द्वारा नोट किया गया है, बी एफ एल की एक संबंधित कंपनी ऑटोमोटिव एक्सल्स लिमिटेड ने भारत को एफ ए ए का निर्यात किया है । एफ ए ए, एफ ए बी और एस के तथा कुछ अन्य घटकों को एक साथ जोड़कर दिए गए नाम के अलावा कुछ नहीं है । याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग समझे जाने के लिए अपात्र हो जाता है क्योंकि संबंधित निर्यातक ने जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है । अन्य घोषित घरेलू उद्योगों के पास सीमलैस ट्यूब्स और पाइप मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय (आई एस एम टी लिमिटेड बनाम भारत संघ 2011 (270) ई एल टी 19 (बॉम्बे)) के निर्णय के आलोक में घरेलू उद्योग संबंधी कोई योग्यता नहीं है ।

ग. कतिपय विशिष्ट मुद्दों के संबंध में अशोक लेयलैंड के अनुरोध

अशोक लेयलैंड द्वारा आयातित मॉडल अद्वितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग किसी अन्य द्वारा नहीं किया जा सकता है । इसके अलावा, अशोक लेयलैंड द्वारा किए गए आयातों के कारण आवेदक उद्योगों से उनकी खरीद में कोई कमी नहीं हुई थी और इसलिए आयातों से याचिकाकर्ताओं को क्षति नहीं हुई ।

घ. सामान्य मुद्दों के संबंध में सभी पांच प्रतिवादियों के अनुरोध

घ.1 संपूर्ण जांच पक्षपात्रपूर्ण है और निम्न के कारण घरेलू उद्योग के पक्ष में है :

क. भारत में आयात नहीं किए गए फर्जी उत्पादों पर शुल्क की अनुशंसा करना ।
 ख. ऐसी दर और तरीके से शुल्क निर्धारित करना जिसका प्रकटन अंतिम जांच परिणाम में नहीं किया गया ।
 ग. निर्यातक के लिए उसके सामान्य मूल्य की तुलना हेतु "समान वस्तु" का निर्धारण और आयातित वस्तु की जांच करके घरेलू उद्योग के निर्धारण की दृष्टि से ।

घ.2 विचाराधीन उत्पाद में भारत में आयात नहीं किए गए उत्पाद शामिल नहीं होंगे-सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क)(1) केन्द्र सरकार को केवल भारत को निर्यात की जा रही "किसी वस्तु" पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करती है परंतु इस जांच में वह उत्पाद शामिल है जिनका भारत में आयात भी नहीं हुआ है, अर्थात :

- (i) फोर्ज एफ ए बी और मशीन एफ ए बी "समान वस्तु" नहीं है क्योंकि उनकी लागत में भारी उतार-चढ़ाव होता है और वे प्रतिस्थापनीय नहीं हैं - केवल मशीन एफ ए बी का भारत में आयात हुआ है और इस प्रकार गैर-मशीन एफ ए बी पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता है ।
- (ii) एफ ए बी और एस के के अद्वितीय मॉडल अन्य मॉडलों के साथ प्रतिस्थापनीय या उनके स्थान पर प्रयुक्त नहीं होते हैं । इसे प्राधिकारी द्वारा भी स्वीकार किया गया है । जब एफ ए बी और एस के के केवल अद्वितीय मॉडलों का ही आयात किया गया है तो जांच में केवल आयातित मॉडल ही शामिल होंगे ।

घ.3 पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन संबंधी गणनाएं निम्नलिखित कारणों की वजह से त्रुटिपूर्ण हैं :-

- (i) एफ ए बी का "फार्जर्ड रूप में" कोई आयात नहीं हुआ है । अतः इस ग्रेड के लिए कोई पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं हो सकता है और इस प्रकार इस उत्पाद पर किसी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए ।
- (ii) जब फोर्जर्ड और मशीन एफ ए बी तथा एस के के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए हैं, तो पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की एकल भारित औसत दर की सिफारिश नहीं की जा सकती है । यह बात केटेलिस्ट मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय (निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम हलदर टोप्सो ए/एस 2000 (120) ई एल टी 11 (एस सी)) के निर्णय के विरुद्ध होगी ।

घ.4 घरेलू उद्योग ने इन मॉडलों के लिए ही एक पृथक क्षति विवरण के लिए सार्वजनिक सुनवाई के दौरान कोई भी तरीका अपनाया है । हम प्राधिकारी से संशोधित विवरण के आधार पर भारत में आयातित मॉडलों के लिए दिए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए क्षति और कारणात्मक संबंधी विश्लेषण निर्धारित करने का अनुरोध करते हैं ।

घ.5 कारणात्मक संबंध से संबंधित विश्लेषण निम्नलिखित कारणों से अत्यधिक त्रुटिपूर्ण हैं :

- (i) याचिकाकर्ता द्वारा अशोक लेयलेंड को बिक्री में उसी अवधि के दौरान कई गुना वृद्धि हुई है जब कथित पाटित आयात हुए थे ।
- (ii) केवल इस बात से कि घरेलू उद्योग ने अन्य मॉडलों की बिक्री मात्राएं गंवाई हैं जिसके कारण उसे लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभों में घाटा हुआ है, क्षति होने का कारण नहीं माना जा सकता है ।
- (iii) इस बात को स्पष्ट करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि एफ ए बी के आयातों में 1456 मी.ट. की वृद्धि से बिक्रियों में 11892 मी.ट. तक की गिरावट कैसे आ सकती है ।
- (iv) इस बात को स्पष्ट करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि एस के के आयातों में 30 मी.ट. की वृद्धि से बिक्रियों में 2080 मी.ट. तक की गिरावट कैसे आ सकती है ।
- (v) अन्य वाहन विनिर्माता याचिकाकर्ता से खरीद नहीं कर रहे हैं जो घरेलू उद्योग को कथित क्षति का एकमात्र कारण रहा है । इसके लिए किसी भी तरह से कथित पाटित आयातों को जिम्मेदार नकीं ठहराया जा सकता है ।

(vi) यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते भी हैं कि कथित आयातों के कारण भी घरेलू उद्योग को क्षति हुई है तो यह आग्रह किया जाता है कि क्षति मार्जिन को मांग में संपुर्चन द्वारा क्षति और कथित आयातों द्वारा क्षति के रूप में अलग-अलग किया जाए और पाटनरोधी शुल्क की अनुशंसा क्षति के केवल उस हिस्से के लिए की जाए जो भारत में पाटित आयातों के कारण हुआ है ।

घ.6 चुनिन्दा संकेतकों हेतु क्तिपय अतार्किक निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए जांच अवधि के बाद के आंकड़ों का प्रयोग न किया जाए । यदि उनका प्रयोग किया भी जाता है तो जांच अवधि के पश्चात दूसरी तिमाही के लिए किया जाना चाहिए ।

घ.7 क्षति रहित कीमत की गणना के लिए विचारित नियोजित पूँजी पर आय अतार्किक है - भारतीय बुनकर एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2004) 170 ई एल टी 144 पर भरोसा किया जाए ।

मै. हुबेर्ड्री-रिंग ऑटो एक्सल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.; मै. हुबेर्ड्री-रिंग फोर्जिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.; मै. हुबेर्ड्री-रिंग मोटर स्टेयरिंग गियर कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.; मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड, भारत और मै. अशोक लेयलैंड लिमिटेड, भारत की ओर से घरेलू उद्योग के अनुरोधों संबंधी खंडन अनुरोध

5. इन हितबद्ध पक्षकारों की ओर से संक्षेप में निम्नलिखित खंडन अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं :

- 100% खरीद चीन जन.गण. से की गई : किसी निर्यातक के चयन में लगी 15-19 महीने की अवधि पर विचार करते हुए यह तर्क दिया गया है कि पाटन के कारण और उसके कारण होने वाली संभावित क्षति सिद्ध होती है । तथापि, दूसरे आपूर्तिकर्ता से सोर्सिंग शुरू करने का निर्णय कच्ची सामग्री के एक स्रोत पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया गया कदम है । याचिकाकर्ता से खरीद वस्तुतः जांच अवधि में भारी वृद्धि दर्शाती है जिससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता को आयातों से क्षति नहीं हुई है । याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि अशोक लेयलैंड ने चीन जन.गण. से लगभग 100% खरीद की योजना बनाई है, गलत है । यह नोट किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता से एफ ए बी और एस के की खरीद में जांच अवधि के दौरान क्रमशः 113% और 226% की वृद्धि हुई है ।
- विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु : याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा विनिर्मित एफ ए बी और एस के के सभी मॉडल आयातित मॉडलों के समान उत्पाद हैं । सामान्य मूल्य के निर्धारण में निर्यातक के इसी दावे को प्राधिकारी ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि इन मॉडलों के बीच "पर्याप्त अंतर" है । इस प्रकार घरेलू उद्योग के दावे को भी अस्वीकार किया जाना चाहिए ।

12924/12-2

- घरेलू उद्योग का गठन : याचिकाकर्ताओं का दावा है कि टाटा मोटर्स ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि एच वी ए एल को घरेलू उद्योग माना जाए, यह दावा गलत है। इस संबंध में टाटा मोटर्स द्वारा प्रस्तुत पत्र सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध है। याचिकाकर्ता ने चीन जन.गण. से धात्विक कोयले के मामले में प्राधिकारी के जांच परिणाम पर अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए भरोसा किया है कि एच.वी ए एल के उत्पादन को एक पृथक बाजा माना जाएगा। तथापि, प्राधिकारी का जांच परिणाम इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। जैसा जांच परिणाम के पैरा 27 में अवलोकन किया गया है, आर आई एन एल जिसे उस मामले में घरेलू उत्पादक मानने की मांग की गई थी, वह संबद्ध वरतु का कोई उत्पादन नहीं कर रहा था। अतः प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग की परिभाषा के परंतुक का सारा विश्लेषण "व्यर्थ" हो जाता है जिसे पूर्व निर्णय नहीं माना जा सकता है। मोहनदास ईसर दास बनाम ए एन सत्तनाथन 2000 (125) ई एल टी 206 (बाम्बे) और दिल्ली नगर निगम बनाम गुरुनाम कौर 1989 ए आई आर 38 (एस सी) पर भरोसा किया गया है। अन्यथा भी धात्विक कोयले के मामले में आर आई एन एल के उत्पादन को आबद्ध खपत माना गया था क्योंकि उनके उत्पादन की खपत अन्य वस्तुओं के उत्पादन की उनकी प्रक्रिया में आंतरिक रूप से हो गई थी। तथापि, टाटा मोटर्स/एच.वी ए एल के मामले में एवं वी ए एल द्वारा उत्पादित एफ ए बी और एस की खपत टाटा मोटर्स द्वारा की जाती है। ये दोनों भिन्न-भिन्न विधिक सत्ताएं हैं। इस प्रकार प्राधिकारी के समक्ष तथ्य पूर्ववर्ती मामले से अब बिल्कुल अलग हैं। पिंग आयरन विनिर्माता एसोसिएशन मामले में सेस्टेट का निर्णय उस मुद्दे पर नहीं है जिसे इस मामले में अब उठाया गया है कि दिए गए तथ्यों में नियम 2(ख) का परंतुक पूरा नहीं होता है। इस प्रकार अब प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया मुद्दा पूर्णतः नया नहीं है।
- चीन में याचिकाकर्ता के संबंधित पक्षकार द्वारा एफ ए बी और एस के का निर्यात: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उसने एफ ए बी या एस के का आयात नहीं किया है परंतु चीन जन.गण. में याचिकाकर्ता के एक संबंधित निर्यातक ने फ्रंट एक्सल एसेम्बली का निर्यात किया है जो एफ ए बी और एस के तथा अन्य संघटकों के आयात के अलावा कुछ नहीं है। अतः याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माने जाने का पात्र नहीं है।
- हुबेई ग्रुप को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करना: याचिकाकर्ता ने बताया है कि हुबेई ग्रुप को एम ई टी प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार द्वारा पर्याप्त शेयरधारित विद्यमान है। तथापि, उसके द्वारा राज्य की पर्याप्त शेयरधारिता का अर्थ यह नहीं है कि सरकार का नियंत्रण विद्यमान है। इस संबंध में अमरीका के अपीलीय निकाय के एक मामले में हाल में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है - चीन से कतिपय उत्पादों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, डब्ल्यू टी/डीएस 379/एबी/आर, 11 मार्च, 2011 जिसमें निम्नानुसार समुक्ति की गई है :

"केवल यह तथ्य कि किसी सत्ता में अधिकांश शेयरधारिता सरकार की है से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि उस सत्ता के कार्यचालन पर सरकार कोई

सार्थक नियंत्रण रखती है बल्कि बात यह है कि सरकार ने उसे मात्र सरकारी प्राधिकार प्रदान किया है"

- याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि निर्यातक ने इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि मूल निविष्टियों की कीमतें बाजार मूल्यों को पर्याप्ततः दर्शाती हैं । परंतु प्रमुख कच्ची सामग्री, स्टील चीन के बाजार में ऐसी कीमतों पर सदैव उपलब्ध होता है जिन पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वह उपलब्ध है । भारत ने स्वयं अन्य के साथ-साथ चीन जन.गण. से स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों और चीन जन.गण. से बाल बियरिंग मामले में चीन के उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया है । अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों को दर्शाने वाली कीमतों पर कच्ची सामग्री के उपलब्ध होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । अतः हुबेर्ग ग्रुप को एम ई टी देने से इंकार नहीं किया जा सकता है ।
- निर्यातकों और आयातकों द्वारा आंकड़ों को छुपाया जाना : याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि निर्यातकों और आयातकों ने उनके बीच व्यापार की मात्रा को पूर्णतः नहीं बताया है । यह दलील वस्तुतः गलत और अनावश्यक है । प्राधिकारी ने निर्यात ब्यौरों का सत्यापन किया है और उसमें कोई भी अंतर ध्यान में नहीं आया है ।
- लंबित आपूर्ति के आदेशों पर विचार किया जाना : याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि आयातकों द्वारा दिए गए ऑर्डर जिन पर आपूर्ति लंबित है, को भी जांच के प्रयोजनार्थ आयात माना जाए । हुबेर्ग ग्रुप और अशोक लेयलैंड ने बताया है कि नवंबर, 2009 के बाद कोई ऑर्डर डिलीवरी हेतु लंबित नहीं है ।
- क्षति और कारणात्मक संबंध : याचिकाकर्ता ने इस बात को ठीक ढंग से उठाया है कि उत्पाद की मांग में गिरावट मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में गिरावट के कारण हुई है । तथापि, यह दलील दी गई है कि उपलब्ध मांग के भीतर घरेलू उद्योग ने अपना बाजार हिस्सा गंवाया है, इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति सिद्ध होती है । याचिकाकर्ता का यह विवरण बताने से ज्यादा छुपाता है । याचिकाकर्ता अशोक लेयलैंड समेत भारत में सभी वाहन विनिर्माताओं को एफ ए बी और एस के की आपूर्ति करता रहा है परंतु अशोक लेयलैंड एकमात्र ऐसा वाहन विनिर्माता है जिसने संबद्ध वस्तु का आयात किया है । यदि याचिकाकर्ताओं पर आयात का प्रभाव पड़ा है तो केवल अशोक लेयलैंड की खरीद पर प्रभाव पड़ना चाहिए । इसके विपरीत अशोक लेयलैंड को संबद्ध वस्तु की बिक्री में जांच अवधि के दौरान क्रमशः 113% और 226% की वृद्धि हुई है जिससे आयातों और कथित क्षति के बीच कोई संबंध नहीं होना सिद्ध होता है ।
- कीमत कटौती : याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भारी कीमत कटौती की जा रही है । अशोक लेयलैंड द्वारा याचिकाकर्ता से एफ ए बी और एस के की खरीद में 113% और 226% की वृद्धि पर विचार करते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कीमत कटौती से याचिकाकर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

- घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड: याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के सभी आर्थिक मापदंडों में विकृति प्रदर्शित हुई है। तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा दर्शाए गए सभी नकारात्मक मापदंड केवल मांग में गिरावट के कारण हैं और न कि आयातों के कारण। मांग में गिरावट के कारण घटे हुए उत्पादन के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई और इस प्रकार याचिकाकर्ता को घाटा हुआ। आयातों से घरेलू उद्योग को किसी भी तरह से कोई क्षति नहीं हुई है।
- वास्तविक क्षति का खतरा : याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यह मामला स्पष्टः सिद्ध करता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा है, यह दावा निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया गया है :-

क. अपेक्षाकृत कम अवधि में आयातों में तीव्र वृद्धि- 6 महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता से एफ.ए.बी के मामले में 113% और एस.के के मामले में 226% की तीव्र वृद्धि खरीद में हुई है।

ख. अशोक लेयलैंड ने चीन जन.गण. से 100% आयात किया है - पूर्णतः विपरीत तथ्यों की दृष्टि से निराधार दावा।

ग. अशोक लेयलैंड की चीन जन.गण. से दीर्घावधिक खरीद योजना - आज के बाजार परिदृश्य में कच्ची सामग्री का 1 से अधिक स्रोत रखना असामान्य नहीं है। इससे याचिकाकर्ता से खरीद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, याचिकाकर्ता से खरीद में कोई गिरावट दिखाई नहीं दी है।

घ. आयातों में अपेक्षाकृत कम अवधि में वृद्धि - दोहराया गया दावा, जिसका ऊपर समाधान कर दिया गया है।

ङ. भारी कीमत कटौती - इससे याचिकाकर्ता से खरीद किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है और याचिकाकर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रयोक्ता उद्योग द्वारा वस्तुओं की खरीद की कीमतें आवेदक की लागत जमा तर्कसंगत लाभ आधार पर आपस में तय की जाती हैं। इस प्रकार आवेदक क्षति का दावा नहीं कर सकता है।

च. हुबेर्ग ग्रुप की क्षमताएं घरेलू मांग से अधिक हैं - एक मिथ्या दावा जिसे साक्ष्यों द्वारा साबित नहीं किया गया है। वस्तुतः निर्यातक अपनी ईष्टतम क्षमता से अधिक पर प्रचालन कर रहा है।

छ. घरेलू बाजार का पर्याप्त हिस्सा निर्यातकों के पास है - केवल अशोक लेयलैंड ने संबद्ध वस्तु का आयात किया है परंतु याचिकाकर्ता भारत में प्रत्येक अन्य वाहन विनिर्माता को इनकी बिक्री कर रहा है। केवल अशोक लेयलैंड द्वारा वस्तु का आयात करने से निर्यातकों

के पास भारी बाजार हिस्सा कैसे हो सकता है। बाजार हिस्से में कमी केवल मांग में संकुचन के कारण उत्पन्न स्थिति की वजह से हुई है।

- कारणात्मक संबंध : नियमावली के अनुबंध-2 और डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.5 की ओर याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिलाए जाने से वस्तुतः निर्यातक का पक्ष मजबूत होता है। ये विनियम प्राधिकारी पर निम्नलिखित दायित्व डालते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन से इतर अन्य कारकों की जांच करेंगे और यह कि इन अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए अनिवार्यतः पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। स्वीकृत रूप से घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संकुचन, घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा और कथित पाटन के कारण हुई है। इस अनुरोध को ध्यान में रखे बिना कि आयातों ने याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है, यदि घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई भी है तो पाटन के कारण हुई क्षति के हिस्से के लिए ही आयातों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और शुल्क की सिफारिश केवल उसी सीमा तक की जाए।
- ई सी के निर्णयों पर भरोसा करना : याचिकाकर्ता ने यह दर्शाने के लिए कुछ ई सी निर्णयों पर भरोसा किया है कि मांग में संकुचन के मामले में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में आई गिरावट मांग में गिरावट की दर के अनुपात में होनी चाहिए और यदि कुछ भी इससे अधिक होता है तो उसके लिए पाटित आयात जिम्मेदार होने चाहिए। याचिकाकर्ता ने वस्तुतः उन मॉडलों की बिक्री बढ़ाई है जिनका आयात किया गया है। अशोक लेयलैंड को बिक्री में वृद्धि इस तथ्य के बावजूद हुई है कि एफ ए बी और एस के बाजार में समग्र रूप से जांच अवधि के दौरान क्रमशः 21% और 25% की गिरावट आई है, जैसा प्राधिकारी द्वारा नोट किया गया है। इस प्रकार समग्र बाजार में गिरावट के बावजूद याचिकाकर्ता भारत में आयातित मॉडलों की बिक्री में वृद्धि करने में सक्षम रहा है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए लिखित अनुरोध

6. घरेलू उद्योग की ओर से संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

1. इस उद्योग में खरीद और बिक्री की प्रक्रिया में विक्रेता विकास अपेक्षित है जिसमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं - उत्पादन और आपूर्ति की क्षमता और योग्यता स्थापित करना, कीमत प्रस्ताव, प्रस्ताव स्वीकृति, खरीद आदेश देना और वाणिज्यिक उत्पादन।
2. चीन के उत्पादकों ने वस्तुतः कम कीमतों का प्रस्ताव किया है और भारतीय बाजार के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है।
3. चीन की कंपनियां यह सिद्ध करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था के माहौल में प्रचालन कर रही हैं। चीन की कंपनियां जिसके "सस्ते" होने का दावा करती हैं, वह "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का लक्षण" है।

12929012-3

4. विचाराधीन उत्पाद में कच्ची सामग्री इस्पात है चीन में जिसकी कीमतें बाजार मूल्यों को पर्याप्तः नहीं दर्शाती हैं ।
5. निर्यातकों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि मूल निविष्टियों की कीमतें बाजार मूल्यों को पर्याप्तः दर्शाती हैं ।
6. चीन जन.गण. में उत्पादकों द्वारा सृजित क्षमताएं उनकी घरेलू मांग से अधिक हैं ।
7. एक ए बी और एस के को 2 भिन्न वस्तुएं माना गया है । एक ए ए (फ्रेंट एक्साल एसेंबली) एक बिल्कुल अलग उत्पाद है ।
8. टी एम एल का उत्पादन पूर्णतः आबद्ध खपत के लिए है और इसलिए वर्तमान प्रयोजन हेतु उस पर विचार नहीं किया जा सकता है ।
9. लंबित आपूर्ति वाले ऑर्डरों पर विचार किया जाना अपेक्षित है ।
10. उपलब्ध मांग के भीतर घरेलू उद्योग को पाठन के कारण अपना बाजार हिस्सा गंवाना पड़ा है ।

घरेलू उद्योग की ओर से खंडन अनुरोध

7. घरेलू उद्योग की ओर से संक्षेप में निम्नलिखित खंडन अनुरोध किए गए हैं :-

1. चीन में निविष्टियों की कीमतें बाजार मूल्यों को पर्याप्तः नहीं दर्शाती हैं । जब चीन के बाजार में कीमतें कम होती हैं तो इसका यह अर्थ है कि चीन के उत्पादकों को आपूर्तिकर्ताओं से उनके संबंध पर विचार किए बिना कृत्रिम रूप से कम कीमतों पर निविष्टियां प्राप्त होती हैं । क्रेता और विक्रेता के बीच संबंध के कारण कीमत का उचित होना और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के कारण कीमत का उचित होना दो बिल्कुल अलग स्थितियां हैं ।
2. ऐसी स्थिति में जहां युप की अनेक कंपनियां विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और/या बिक्री में शामिल हैं, ऐसी सभी कंपनियों को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने से पहले जांच की जाए । स्वीकृत रूप से समग्र समूह ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है ।
3. कंपनी में प्रमुख प्रबंधन कार्मिक चीन सरकार के सीधे पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन है । इस प्रकार राज्य के हस्तक्षेप से इंकार नहीं किया जा सकता है ।
4. विचाराधीन उत्पाद में कच्ची सामग्री इस्पात है जिसकी कीमतें चीन में बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाती हैं । इस्पात, उत्पादन लागत का 70-80% हिस्सा होता है । इसके अलावा, इस्पात के उत्पादन में प्रयुक्त कोयले और कोक की कीमतें भी चीन में बाजार मूल्यों को नहीं दर्शाती हैं ।
5. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को प्रदत्त सब्सिडी यद्यपि, सब्सिडी जांच की विषय वर्तु है, तथापि, तर्दर्थ रूप से सब्सिडी प्रदान करना कच्ची सामग्री के उत्पादकों को

सहायता देना या उसके बाद निविष्टि के आपूर्तिकर्ताओं को सहायता देना सभिंडी जांच की विषय वस्तु नहीं है ।

6. टी एम एल का उत्पादन पूर्णतः आबद्ध खपत के लिए है और इसलिए वर्तमान प्रयोजन हेतु उस पर विचार नहीं किया जा सकता है । टी एम एल के आबद्ध उत्पादन को योग्यता के प्रयोजन से बाहर रखा जाना अपेक्षित है । इसके होते हुए भी उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा "एक प्रमुख हिस्सा" बनता है ।
7. घरेलू उद्योग को हुई क्षति और अधिक हो जाएगी यदि केवल ए एल एल से संबंधित कार्यकलापों संबंधी सूचना पर विचार किया जाता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए सभी किस्मों और सभी क्रेताओं पर विचार करते हुए क्षति निर्धारित करना अपेक्षित है ।
8. यह तथ्य कि आयातों में ऐसी स्थिति में वृद्धि हुई है जब मांग में गिरावट आई है, से कम से कम बढ़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को बढ़ी हुई क्षति सिद्ध होती है । यद्यपि घरेलू उद्योग पहले से ही मांग में कमी का सामना कर रहा था । बढ़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग की मुश्किलों में और वृद्धि हो गई ।
9. उपभोक्ता ने जांच अवधि के बाद आयातित सामग्री की भारी मात्रा की खपत की है । उस दृष्टि से घरेलू उद्योग को जांच अवधि के पश्चात सामग्री की बिक्री के अवसर तब भी गंवाने पड़े हैं जब उपभोक्ता उत्पादन कर रहा था ।
10. आयात 2008-09 के बाद भी जारी रहे हैं आयात अब तक भी जारी हैं अलबत्ता भिन्न-भिन्न मात्राओं में ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

8. सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे जैसा उनके लिखित अनुरोधों में प्रदर्शित है और तत्संबंधी खंडन अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है ।

- प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन के निर्यातकों के एम ई टी के दर्जे के दावे की प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जांच की गई थी परंतु अंतिम जांच परिणामों के पैरा 25 से 42 में अविलेखबद्ध कारणों की वजह से उसे स्वीकार नहीं किया गया और उन पर ही भरोसा किया गया । हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया कि अधिक "राज्य शेयरधारिता" का अर्थ किसी कंपनी में "राज्य का हस्तक्षेप" नहीं है । तथापि, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकार इस दायित्व को पूरा नहीं करते हैं जो उन पर यह सिद्ध करने के लिए है कि उनकी कंपनी में भारी राज्य धारिता होने पर भी वह बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार की दावेदार हैं । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उन्होंने

यह राय नहीं दी है कि क्या चीन की सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है; बल्कि प्राधिकारी ने इस विषय के संबंध में पाटनरोधी नियमों और विनियमों की दृष्टि से अपने जांच परिणामों को आधारित किया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि एक पूर्व धारणा होगी कि कोई देश जिसे जांच से पहले तीन वर्षों की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या किसी डब्ल्यू टी औ सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया हो या माना गया हो तो उसे गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाएगा। तथापि, बशर्ते कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश की संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना या साक्ष्य उपलब्ध कराके ऐसी धारणा का खंडन करें जो यह सिद्ध करती हो कि वह देश उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है। यह नोट किया जाता है कि चीन के निर्यातिक वर्तमान मामले में इस धारणा का खंडन करने में विफल रहे हैं।

- यह भी दलील दी गई है कि प्राधिकारी ने धारा 9 क (6) के उपबंधों की उपेक्षा की है। चीन के निर्यातिकों द्वारा धारा 9 (6) की दी गई व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह दलील संविधियों की व्याख्या के मूल नियम द्वारा समर्थित नहीं है। धारा 9 क (6) एक सामान्य उपबंध है जो केवल यह बताता है कि किसी निर्यातिक या उत्पादक द्वारा निर्यातित किसी वस्तु से संबंधित पाटन मार्जिन ऐसे निर्यातिक या उत्पादक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड्स और असहयोगी निर्यातिकों या उत्पादकों के मामले में उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। दूसरी ओर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 और 8 विशेष रूप से "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था" के मामलों में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की गणना से संबंधित है। व्याख्या का यह एक स्वीकृत नियम है कि विशेष प्रावधान सामान्य प्रावधान को अतिव्याप्त करता है। इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि उन्होंने पाटनरोधी नियमावली द्वारा यथानिर्धारित गैर बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की सही ढंग से गणना की है।
- गोपनीयता से संबंधित मुद्दे के बारे में चूंकि परिकलित सामान्य मूल्य अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू उद्योग की गोपनीय सूचना पर आधारित होता है, इसलिए उसका प्रकटन नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों की प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जांच की गई है और संतुष्ट होने पर उन्हें पाटनरोधी नियमावली के पैरा 7 के अनुसार स्वीकार किया गया है।
- इस दलील के संबंध में कि मै. गार्ड फोर्ज लि. घरेलू उद्योग नहीं है क्योंकि टाटा मोटर्स के 64.23% के हिस्से के मुकाबले कुल उत्पादन में उनका हिस्सा मात्र 28.17% बनता है; प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में जांच परिणाम जारी करते समय इस मुद्दे की विधिवत रूप से जांच की गई है। प्राधिकारी इस विषय के संबंध में अपने अंतिम जांच परिणामों के पैरा 17 पर भरोसा करते हैं जिसमें यह नोट किया गया है कि (क) आवेदक द्वारा प्रत्येक संबद्ध वस्तु का उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। (ख) आवेदक द्वारा तथा उसके साथ के समर्थकों द्वारा प्रत्येक संबद्ध वस्तु का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 50% से अधिक बनता है। (ग)

यह कि यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से किया गया है। इस प्रकार मैं भारत फोर्ज लि., पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर प्रत्येक विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग है।

- इस तर्क के संबंध में कि अशोक लेयलैंड द्वारा आयातित मॉडल अद्वितीय वस्तुएं हैं जिनका किसी अन्य द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है और यह कि अशोक लेयलैंड द्वारा आयात के कारण आवेदक उद्योग से उनकी खरीद में कमी नहीं आई है और इस प्रकार आवेदक उद्योग को आयातों से क्षति नहीं हुई है; प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस दलील में कोई तर्कधार नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग को स्पष्ट रूप से संबद्ध देश से आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु की कम कीमतों के कारण संबद्ध वस्तु के आर्डर गंवाने पड़े हैं। मैं अशोक लेयलैंड का यह दावा नहीं है कि घरेलू उद्योग जांचाधीन वस्तु की उन्हें आपूर्ति करने में अक्षम है।
- इस तर्क के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद में भारत में आयात नहीं किए गए उत्पादों को शामिल नहीं करना चाहिए और यह कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणनाएं त्रुटिपूर्ण हैं; प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क गुमराह करने वाला है। यहां यह बताना संगत होगा कि पाटनरोधी जांच विचाराधीन उत्पाद अर्थात् "भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए फ्रंट एक्सल बीम और स्टेयरिंग नकल्स" के संबंध में की गई थी और वस्तुतः यह पाया गया था कि संबद्ध वस्तुओं का पाटन हो रहा है और घरेलू उद्योग को इसके परिणामस्वरूप क्षति हो रही है। अतः प्राधिकारी ने इस विषय पर संगत नियमों और विनियमों के अनुसार विचाराधीन उत्पादों पर शुल्क की सिफारिश की थी। यह कहना गलत है कि जांच विचाराधीन उत्पाद की किसी विशेष किस्म तक सीमित है जिसे जांच अवधि के दौरान पाटित किया गया है। यदि ऐसे किसी तर्क को स्वीकार किया जाए तो इससे लागू किए गए पाटनरोधी उपायों का प्रवर्चन होगा और पूरी प्रक्रिया जिसे विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समाधान करने के लिए शुरू किया गया है, व्यर्थ हो जाएगी।
- कारणात्मक संबंध विश्लेषण के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने देश में उत्पाद की मांग में विभिन्न पक्षकारों के बाजार हिस्से पर विचार करके घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रभाव का विश्लेषण किया है। तत्पश्चात् प्राधिकारी द्वारा यह अवलोकन किया गया कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में अक्टू-दिसंबर, 2008 (जांच अवधि पश्चात) की अवधि में उसके बाजार हिस्से में और अधिक गिरावट प्रदर्शित हुई। अंतिम जांच परिणामों के पैरा 95 में यह नोट किया गया कि घरेलू उद्योग ने उपलब्ध मांग में बाजार हिस्सा गंवाया है। तदनुसार प्राधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि घरेलू उद्योग गिरती हुई मांग की समस्या का पहले से सामना कर रहा था, परंतु पाटित आयातों के कारण यह और बढ़ गई थी।
- यह दलील कि वर्ष 2007-08 के दौरान किए गए आयात की मात्रा बहुत कम थी, तथ्यहीन है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों के पैरा 64 से 72 में मात्रात्मक प्रभाव की जांच की है जिन पर भरोसा किया गया है।

1292 4/12-4

- वास्तविक क्षति के खतरे के बारे में यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -II के पैरा VII के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी के लिए इसमें निर्धारित कारकों की जांच करना अपेक्षित है जिनमें अन्य के साथ-साथ भारत में पाटित आयातों की वृद्धि दर जो भारतीय बाजारों को पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना दर्शाती हो, शामिल है और यह कि क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर पर्याप्त न्यूनकारी और हासकारी प्रभाव पड़ेगा, और उनसे आगे आयातों की मांग बढ़ने की संभावना होगी। रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों जिन्हें अंतिम जांच परिणामों के पैरा 94 में दर्शाया गया है, अपेक्षाकृत अल्प अवधि में आयातों में तीव्र वृद्धि को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं जैसा संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंधित बाजार हिस्से से भी सिद्ध हुआ था। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि चीन जन.गण. में उत्पादकों द्वारा सृजित क्षमताएं उनकी घरेलू मांग से अधिक थीं। अतः चीन जन.गण. से देश में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के प्रवाह की संभावना स्पष्ट रूप से साबित मानी गई थी।
- इस तर्क के संबंध में कि क्षति रहित कीमत का त्रुटिपूर्ण निर्धारण हुआ है, यह पूर्णतः तथ्यहीन है क्योंकि प्राधिकारी ने पिछले काफी समय से अपनाई जा रही अपनी संगत प्रक्रिया के अनुसार क्षति रहित कीमत की गणना की है।
- प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति संबंधी विश्लेषण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के साथ पठित नियम-11 के अंतर्गत यथापेक्षित प्राधिकरी द्वारा पर्याप्त ध्यान देकर किया गया है।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां

9. मै. हुबेर्ड्राई-रिंग ऑटो एक्सल कं. लि.; मै. हुबेर्ड्राई-रिंग फोर्जिंग कं. लि.; मै. हुबेर्ड्राई-रिंग मोटर स्टेयरिंग गियर कंपनी लि.; मै. टाटा मोटर्स लि., इंडिया तथा मै. अशोक लेयलेंड लि., इंडिया की ओर से संक्षिप्त में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:-

- प्रकटन विवरण का उत्तर देने के लिए बहुत कम समय दिया गया है।
- यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा उठाए गए निम्नलिखित मुद्दों का समाधान नहीं किया गया है।
- यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने एफ ए बी के दो मॉडलों तथा एस के के तीन मॉडलों जिनका आयात भारत में किया गया था, के लिए पृथक हानि विवरण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई के दौरान लिखित आश्वासनदिया। हालांकि ऐसी कोई हानि की सूचना प्रकटन विवरण में नहीं देखी गई है।
- यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध वस्तुओं अर्थात् मशीन से बनाए हुए तथा फोर्ज किए गए दो अलग-अलग प्रकार हैं जो मूल्य और भार के मामले में पर्याप्त रूप से अलग-अलग हैं और इसलिए पृथक पाटन और हानि मार्जिन तथा पाटनरोधी शुल्क की अलग दर का निर्धारण उनके लिए किया जाना चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम हल्दोर

टॉप्सो में माननीय उच्चतम न्यायालय का संदर्भ दिया गया है, आंध पैट्रोकैमिकल्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में लिए गए निर्णय को देखते हुए यह तर्क दिया गया है कि भारत में आयात न किए गए मॉडल पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता ।

- इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा ब्रिजस्टोन इंडिया प्रा. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में लिए गए निर्णयों का संदर्भ देते हुए यह अनुरोध किया गया है कि एन आई पी की गणना करते समय घरेलू उद्योग को 22% की अत्यधिक आय की अनुमति न दी जाए ।

बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबंध

- यह तर्क दिया गया है कि सभी निदेशक शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित होते हैं और लगभग 43,000 शेयर होल्डर हैं । शेयर होल्डरों की भारी संख्या तथा इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए अपेक्षित कोई कच्चा माल सरकारी नियंत्रण वाली किसी कंपनी से नहीं खरीदा जाता है, यह दर्शाता है कि निदेशक सरकार द्वारा प्रभावित नहीं हैं । संबद्ध वस्तुओं के लिए प्रमुख कच्चा माल इस्पात है । भारतीय प्राधिकरण ने विगत में चीन के इस्पात का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के समतुल्य माना है तथा इसलिए स्वीकृत तथ्य की पुष्टि नहीं करने में कोई विशिष्ट कमी नहीं है ।

लेखा पंजी के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण

- सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 9 क (6 क) का संदर्भ लेते हुए, यह तर्क दिया गया है कि यह कानून की स्थापित परंपरा है कि किसी अधिनियम के प्रावधान उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों से ऊपर होगा । सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 एक व्यापक संविधि है और नियम एक प्रत्यायोजित विधान है और इसलिए इन दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति में व्यापक संविधि मान्य होगी । इसलिए यह तर्क दिया गया है कि सामान्य मूल्य निर्यातक के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण निर्यातक द्वारा रखे गए लेखा पंजी के अनुसार किया जाए ।

सामान्य मूल्य का प्रकटन

- यह तर्क दिया गया है कि किसी उत्पाद का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गोपनीय कैसे रखा जा सकता है ।

घरेलू उद्योग के संघटक

- यह तर्क दिया गया है कि नियम 2(ख) का पहला परंतु की प्रयोज्यता पर चर्चा नहीं की गई है । यू एस कॉटन यार्न (डी एस 192 आर) के मामले में डब्ल्यू टी ओ के पैनल रिपोर्ट का उदाहरण दिया गया है ।

- यह तर्क दिया गया है कि यह सिद्धांत कि कोई आदेश जिसमें कानूनी प्रावधानों पर विचार नहीं किया जाता हो और हितबद्ध पक्षकार द्वारा उठाए गए तर्क गोपनीय आदेश है जिसके फलस्वरूप केवल मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है । केवल 28 प्रतिशत शेयर होलिंग उत्पादक को इस संविधि के तात्पर्य के अधीन "घरेलू उद्योग" के रूप में नहीं माना जा सकता है । चीन से सीमलैस ट्यूब्स एंड पाइप्स के आयात पर पाटनरोधी शुल्क का उदाहरण दिया गया है (दिनांक 18 नवंबर, 2010 का समाप्ति करण अधिसूचना सं. फा. सं. 14/55/2009-डी जी ए डी) ।

कारणात्मक संबंध

- यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने भारत में किए गए आयात के कारण किसी आदेश को नहीं खोया है । इससे आगे किसी अन्य वाहन विनिर्माता के आदेश के समाप्त होने का कारण संबद्ध आयात नहीं हो सकता है क्योंकि कोई अन्य वाहन विनिर्माताओं ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है इसलिए संबद्ध आयात से घरेलू उद्योग को कोई हानि नहीं हुई है ।

शुल्क की दर

- विचाराधीन उत्पाद या तो "फोर्ज्ड" अथवा "मशीन्ड" हो सकता है । इन दो प्रकारों के लिए उत्पादन लागत तथा निर्यात मूल्य अलग-अलग हैं । निम्न श्रेणी का बिक्री मूल्य अलग-अलग जब हो तब यह तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क की एक दर नहीं लगाई जा सकती है ।

पाटन की पुनरावृत्ति

- जैसा कि प्राधिकारी द्वारा सही तरीके से उल्लेख किया गया है, हानि का खतरा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के पैरा (VII) के अनुसार निर्धारित किया जाना है । प्राधिकारी द्वारा हानि की पुनरावृत्ति के संबंध में पहुंचे गए निष्कर्षों के संदर्भ में हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे निम्नलिखित सूचना एवं स्रोतों जिससे उन्हें प्राप्त किया गया है, को प्रकट करें; चीन जन.गण. में क्षमता मांग संबद्ध वस्तुओं के लिए चीन के बाजार का आकार से अधिक है; चीन जन.गण. में क्षमता और इन आंकड़ों के स्रोत तथा इसकी प्रमाणिकता की जांच अथवा इसे प्रकट नहीं किया गया है । जब सहयोगी निर्यातक विनिर्माता स्टीयरिंग नकल्स जांच की अवधि के दौरान 92% क्षमता उपयोग पर तथा पूर्ववर्ती वर्ष के तत्काल बाद के दौरान 94% क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा था, प्राधिकारी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते थे कि घरेलू उद्योग को हानि उत्पन्न करने के लिए मुक्त रूप से बेचने योग्य क्षमता है ।

10. घरेलू उद्योग की ओर से संक्षिप्त में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है

- घरेलू उद्योग ने जांच के संबंध में विभिन्न मुद्दों के संबंध में अपने अनुरोध को बार-बार दोहराया है और आगे विपक्षी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर अपने दृष्टिकोण की पुष्टि की है ।

- यह तर्क दिया गया है कि इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी से यह अपेक्षा है कि वह (क) क्या उत्पादन और खपत के संबंध में अथवा पूर्ण रूप से आयातों में वृद्धि हुई है तथा (ख) क्या विचाराधीन उत्पाद के आयात से मूल्य में कमी हो रही है अथवा इस प्रकार से पारित आयातों का प्रभाव मूल्यों को कम कर रहा था, पर विचार करे । यदि हां, तो प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह अनेक आर्थिक मानदंडों के संबंध में पारित आयातों के परवर्ती प्रभाव पर विचार करे । स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर पारित आयातों का परवर्ती प्रभाव प्रतिकूल और पर्याप्त रहा है ।
- घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि अशोक लेयलैंड को घरेलू उद्योग की बिक्री काफी गिरी है तथा वह घरेलू उद्योग को हुई हानि को दर्शाता है ।
- घरेलू उद्योग को हानि का निर्धारण अलग-अलग मॉडलों के संबंध में अलग-अलग रूप में नहीं किया जा सकता है । समान वस्तु के संबंध में हानि का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है । उत्पाद के अनेक विभिन्न रूपों की मौजूदगी से केवल यह अर्थ निकलता है कि प्राधिकारी उस पर पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन के लिए विचार करेगा तथा मॉडल विश्लेषण द्वारा मॉडल को अपने कब्जे में लेगा । किसी भी मामले में हानि का विश्लेषण समान वस्तु के लिए किया जाना अपेक्षित है । यदि अंततोगत्वा पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण संपूर्ण रूप में उत्पाद के लिए किया जाना अपेक्षित होता है । विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों/मॉडलों के मूल्यों में भारी अंतर होने का अर्थ यह होता है कि वे समान वस्तु नहीं हैं । केवल पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन के उद्देश्य से अधिकारी द्वारा मॉडल तुलना के माध्यम से मॉडल पर विचार करना अपेक्षित है ।
- कम मूल्य के आयात के स्रोत के कारण मैं अशोक लेयलैंड को अपनी बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए चीन जन.गण. से आयात करना पड़ा ।
- याचिकाकर्ता के आधार को "भारतीय उत्पादन" के संदर्भ में और न कि "घरेलू बाजार के लिए उत्पादन" के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है । एच वी ए एल का उत्पादन को दरकिनार किया जाना अपेक्षित है । यदि इस पर भी विचार किया जाता है कि यह आबद्ध उपभोग नहीं है तथा टाटा मोटर्स एवं एच वी ए एल दो अलग-अलग परंतु संबद्ध कंपनियां हैं । नियम 2(ख) परंतुक मैं इस स्थिति से निपटने का प्रावधान है जहां बाजार दो अथवा उससे अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों में बंटा हुआ हो ।
- फ्रंट एक्सल असेम्बली, फ्रंट एक्सल बीम अथवा स्टीयरिंग नकल से अलग है । प्राधिकारी ने फ्रंट एक्सल बीम अथवा स्टीयरिंग नकल को एक समान वस्तु नहीं माना है । प्राधिकारी ने इन पर संयुक्त जांच के द्वारा जांच की जा रही स्पष्ट रूप से अलग-अलग वस्तु के रूप में विचार किया है । फ्रंट एक्सल बीम अथवा स्टीयरिंग नकल को फ्रंट एक्सल असेम्बली की तरह समान वस्तु के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है ।

1292 9/12-5

- बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित करने की जिम्मेदारी उस स्थिति में प्रतिवादी कंपनी पर है जब एक से अधिक कंपनी उत्पादन अथवा बिक्री में लगे हों। अतः प्राधिकारी को प्रश्नावली का उत्तर तभी स्वीकार करना चाहिए यदि संपूर्ण रूप में इस समूह ने उत्तर प्रस्तुत किया है। यूकि उत्पादन और बिक्री में लगी अन्य समूह कंपनियों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए किसी भी स्थिति में प्राधिकारी को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के लिए दावे को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में जहां शेयर हॉल्डिंग राज्य द्वारा है, नियांतक को न केवल विगत कार्रवाई में बल्कि भविष्य में भी किसी संभावना की स्थिति में हस्तक्षेप अथवा नियंत्रण के न होने को सिद्ध करना होता है। इस संबंध में नियांतक द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। नियांतक ने यह सिद्ध किया है कि इनपुट्स का मूल्य बाजार मूल्य में पर्याप्त रूप से परिलक्षित होता है।
- उस स्थिति में जहां उत्पाद के लिए मूल्य कम हुआ हो और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ हो तथा आयात की मांग स्पष्ट रूप से बढ़ी हो, यह सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को हानि पाटित आयात के कारण हुई है। नियमों के अंतर्गत पाटित आयात के प्रतिकूल परिणामी प्रभाव नियम के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी आर्थिक मानदंड में नहीं देखा जा सकता है। ख्वतः मंदी के बावजूद आयात में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हानि पहुंची है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

11. प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच निम्न प्रकार से की गई है :-

- प्राधिकारी नोट करते हैं कि समय की कमी के कारण हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण का उत्तर देने के लिए बहुत कम समय दिया गया था। हालांकि अनेक अवसर हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के दौरान समय-समय पर अपने अनुरोध दायर करने के लिए प्रदान किए गए हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने कोई महत्वपूर्ण नया मुद्दा नहीं उठाया है और स्पष्ट रूप से उन्हें प्रकटन विवरण का उत्तर देने के लिए कम अवधि देकर कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है।
- प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने एफ ए बी के दो मॉडलों तथा एस के के 3 मॉडलों जिनका आयात भारत में किया गया था, के लिए अलग हानि विवरण देने के लिए कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है।
- आगे यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं अर्थात फ्रेंट एक्सल बीम तथा स्टीयरिंग नकल्स के दो अलग-अलग प्रकार हैं और मशीन्ड अथवा फोर्जर्ड के रूप में वे नहीं हैं जैसा कि प्रतिवादी द्वारा तर्क दिया गया है। जबकि प्राधिकारी किसी दिए गए मामले में पी सी एन आधार पर पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन का अपना निश्लेषण कर

सकता है लेकिन जांच इसका निर्धारण करने के लिए की जाती है कि क्या विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया गया है तथा क्या इससे घरेलू उद्योग को हानि होती रही है अथवा नहीं । इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा दिये गए तर्कों में कोई दम नहीं है ।

- जहां तक एम ई टी का दावे का संबंध है, प्राधिकारी इस बात को दोहराते हैं कि चीन के निर्यातकों का एम ई टी दर्ज के दावे की विधिवत जांच प्राधिकारी द्वारा की गई थी लेकिन उसे अंतिम निष्कर्षों के पैरा 24-42 में दर्ज किए गए कारणों से स्वीकार नहीं किया गया था तथा उन पर विश्वास किया जा रहा है । हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि पर्याप्त "राज्य का शेयर धारक" से किसी कंपनी में "राज्य का हस्तक्षेप" नहीं होता है । हालांकि यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकार यह जिम्मेदारी नहीं निभा पाए जो उन पर यह साबित करने के लिए है कि इसकी कंपनी में पर्याप्त शेयर धारक को ध्यान में रखे बिना बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबंध करने का उन्हें हक है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि इसने यह मत नहीं व्यक्त नहीं किया है कि क्या चीन की सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है बल्कि प्राधिकारी ने इस विषय पर पाटनरोधी नियमों और विनियमों के संबंध में अपने निष्कर्षों को आधार बनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यह पूर्वानुमान होगा कि किसी देश जिसे होना निर्धारित किया गया है अथवा जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य देश द्वारा इस जांच के पूर्व के तीन वर्षों के दौरान पाटनरोधी जांच के प्रयोजन से एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया हो । हालांकि बशर्ते कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश अथवा ऐसे देश के संबंधित प्रतिष्ठान निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना एवं साक्ष्य प्रदान कर ऐसे पूर्वानुमान का खंडन कर सकते हैं जो यह सिद्ध करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है । यह नोट किया गया है कि चीन के निर्यातक वर्तमान मामले में इस पूर्वानुमान का खंडन नहीं कर पाए ।
- धारा 9 क (6 क) के संबंध में, प्राधिकारी दोहराते हैं कि चीन के निर्यातकों द्वारा धारा 9 क (6 क) के संबंध में दी गई व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसे तर्क को संविधियों की व्याख्या के मौलिक नियमों द्वारा समर्थन नहीं किया गया है । धारा 9 क (6 क) एक सामान्य प्रावधान है जिसमें केवल इस बात का उल्लेख है कि किसी निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा निर्यात की गई किसी वस्तु के संबंध में पाटन के मार्जिन का निर्धारण ऐसे निर्यातकों अथवा उत्पादकों द्वारा रखे गए अभिलेखों तथा गैर सहयोगी निर्यातक अथवा उत्पादक के मामले में उपलब्ध सूचना के आधार पर किया जाएगा । दूसरी ओर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 7 एवं 8 में "गैर बाजार अर्थव्यवस्था" के मामले में सामान्य मूल्य तथा निर्यात मूल्य की गणना विशिष्ट रूप से की जाती है । इसलिए प्राधिकारी का यह विचार है कि इसने पाटनरोधी नियमावली द्वारा यथा निर्धारित गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य तथा निर्यात मूल्य की सही-सही गणना की है ।
- गोपनीयता से संबंधित मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी अपना दृष्टिकोण दोहराते हैं कि चूंकि सामान्य मूल्य अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू उद्योग की गोपनीय सूचना के आधार पर

बनाई गई थी, इसलिए उसे प्रकट नहीं किया जा सकता था। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए गोष्ठनीयता के दावे की विधिवत जांच प्राधिकारी द्वारा की गई थी तथा इसकी संतुष्टि के आधार पर ही इसे पाटनरोधी नियमावली के पैरा 7 के संबंध में स्वीकार किया गया था।

- घरेलू उद्योग के संघटकों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली के संबंध में, मै. भारत फोर्जर्ड लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2(ख) के आशय से विचाराधीन प्रत्येक उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग का हिस्सा है।
- हानि तथा कारणात्मक संबंध के विश्लेषण के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने देश में उत्पादों की मांग में विभिन्न पक्षकारों के बाजार हिस्से पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रभाव का विश्लेषण किया है, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों ने अक्टूबर-दिसंबर, 2008 की अवधि में (पी ओ आई के बाद) इसके बाजार हिस्से में और गिरावट दर्शायी है। अंतिम निष्कर्ष के पैरा 95 में नोट किया गया था कि उपलब्ध मांग के भीतर घरेलू उद्योग को अपने बाजार हिस्से का नुकसान हुआ है। तदनुसार प्राधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि घरेलू उद्योग गिरती हुई मांग की समस्या का पहले से ही सामना कर रहा था लेकिन वह पाटित आयातों से और अधिक बढ़ गया था। 5 मार्च, 2010 के अंतिम निष्कर्ष में यथापरिलक्षित विश्लेषण पर विश्वास किया जा रहा है।
- अत्यधिक हानि के खतरे के संबंध में यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-2 का पैरा VII के संबंध में पर्याप्त हानि के खतरे के निर्धारण के उद्देश्य से प्राधिकारी को उसमें निर्धारित कारकों की जांच करना आवश्यक होता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से बढ़े पाटित आयातों की संभावना को दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की दर शामिल है तथा यह भी कि क्या आयात उन मूल्यों पर हो रहा है जिनका घरेलू मूल्यों को कम करने पर व्यापक प्रभाव होगा तथा इससे और आगे आयात की मांग बढ़ने की संभावना होगी। रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि बहुत कम समय में आयात में अचानक वृद्धि हुई है जो संबद्ध वस्तुओं के आयात का तुलनात्मक बाजार हिस्से से भी स्पष्ट होता है। इसके अलावा, यह नोट किया गया था कि चीन जन.गण. में उत्पादकों द्वारा सृजित क्षमताएं उनकी घरेलू मांग से अधिक थी। इसलिए चीन जन.गण. से इस देश में होने वाले पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा की संभावना स्पष्ट रूप से स्थापित होती हुई देखी गई थी। यह आवश्यक नहीं है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के पैरा VII में यथापरिलक्षित सभी कारक अनिवार्य रूप से प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाते हैं।
- इस तर्क के संबंध में कि एन आई पी का निर्धारण सही नहीं हुआ है, प्राधिकारी दोहराते हैं कि इस तर्क में कोई दम नहीं है और यह कि प्राधिकारी ने इसकी सतत प्रथा के अनुसार क्षति रहित मूल्य की गणना की है।

12. इस विषय पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए अनुरोधों की सावधानीपूर्वक जांच करने और मामले के विधिक प्रावधानों और तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि अविलेखबद्ध तथ्य दिनांक 5 मार्च, 2010 के अंतिम जांच परिणामों में किसी संशोधन को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं।

निष्कर्ष

13. माननीय सेस्टेट के आदेशों के अनुसार सभी पक्षकारों को मौखिक और लिखित अनुरोध करने का अवसर देने के पश्चात प्राधिकारी ने ऊपर दिए गए पैराओं में उनकी जांच की है। सभी पक्षकारों के अनुरोधों की जांच करने के बाद प्राधिकारी पूर्व में निर्धारित और दिनांक 5 मार्च, 2010 के अंतिम जांच परिणामों में उल्लिखित निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

14. अतः प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना की तारीख से संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश की पुष्टि करते हैं। प्राधिकारी का यह भी निष्कर्ष है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की संगत अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2012

(Final Findings)

Subject : Post-Decisional Oral Hearing on Anti-Dumping Investigations concerning imports of 'Front Axle Beam and Steering Knuckles meant for heavy and medium commercial vehicles' originating in or exported from China PR—Final findings.

Order No. 14/19/2008-DGAD.—In pursuance of the Hon'ble Tribunal (CESTAT's) Final order No. AD/31-51/2011-AD dated 11th August, 2011, a post-decisional hearing was held on 23rd January, 2012 on the captioned subject, wherein the interested parties that had participated in the instant investigation were requested to participate.

2. Upon conclusion of the said hearing, the interested parties that had made their oral submissions were advised to file the written submissions within the stipulated time as per the AD Rules. They were also advised to file the rejoinders thereafter.

3. The written submissions and rejoinders filed by the interested parties, to the extent considered relevant, have been duly considered in this order. Submissions made by interested parties have been examined by the Authority as follows:

Written Submissions made on behalf of M/s. Hubei Tri-Ring Auto Axle Co. Ltd., China PR; M/s. Hubei Tri-Ring Forging Co. Ltd., China PR; M/s Hubei Tri-Ring Motor Steering Gear Co. Ltd, China PR; M/s TATA Motors Ltd, India and M/s Ashok Leyland Ltd, India

4. The following submissions, in brief, have been made on behalf of these interested parties:

Submissions by Hubei Group concerning issues specific to them

A.1. Participation in the hearing was under protest and without prejudice to the SLPs pending before the Hon'ble Supreme Court.

A.2. Denial of market economy treatment is unjustified for the following reasons:

- (i) *Mere share-holding by the Government cannot be regarded as dis-qualify the exporter from operating under Market Economy conditions - Court of First Instance of the European Communities (Fourth Chamber) in Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd. v. Council for the European Union (17 June 2009)*
- (ii) *The Authority itself has granted MET to LISCO, a Chinese producer in the AD investigation concerning imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel inter alia from China PR and to Chinese exporters in Ball Bearings case. The previous decisions of the Authority clearly show that steel prices in China PR do reflect their true market value.*

A.3. AD Duty cannot be imposed to remedy injury alleged to have been caused due to subsidies alleged to have been provided by Chinese Government.

A.4. Normal value determination cannot be kept confidential - Names of major inputs and its international prices cannot be considered confidential.

B Submissions made by TATA Motors

B.1. The petitioner does not constitute domestic industry as its total share in production is a mere 28.17% as against the share of TATA Motors amounting to 64.23%.

B.2. The application was not made by the domestic industry as required under Explanation to Rule 5(3)(b)

B.3. TATA Motors/ HVAL is in fact a domestic producer – The Authority cannot disregard TATA Motors/ HVAL as a producers because:

- (i) *HVAL and TATA Motors are two different legal entities. There cannot be Captive consumption amongst two different legal entities.*
- (ii) *Mere procurement of entire produce of one Company by another Company cannot be termed as captive consumption. HVAL can supply FABs and SKs to any vehicle manufacturer if suitable orders are received.*
- (iii) *To treat procurement of TATA Motors/HVAL as separate market is clearly against the provisions of Rule 2(b) of the AD Rules as the second condition mentioned therein for considering a market to be a separate market is not satisfied.*
- (vi) *CESTAT ruling in Pig Iron Mfrs Assn's case cannot be applied in present case as in that case the same party has captively consumed the product. In the instant case, FAB and SK have been produced by HVAL and sold to TATA Motors. WTO Panel ruling in US: Cotton Yarn [DS 192R] relied upon*

B:4. The petitioner is related to an exporter of subject goods in China PR - As noted by the Authority in para 17.2 of the final finding, Automotive Axles Ltd a related company of BFL, had exported FAAs to India. FAAs are nothing but FABs and SKs and a few other components assembled together. The petitioner becomes ineligible for being regarded as domestic industry as the related exporter has exported the product under consideration in the investigation. Other proclaimed Domestic Producers do not have any standing in the light of the decision of Designated Authority in the case of seamless tubes and pipes is merged with the judgment of the Hon'ble High Court of Bombay [ISMT Limited v. UOI 2011 (270) E.L.T. 19 (Bom.)].

C Submissions by Ashok Leyland on certain specific issues

Models imported by Ashok Leyland are unique articles which cannot be used anyone else. Further, imports by Ashok Leyland did not lead to a decline in their purchases from the applicant industry and therefore the imports have not injured the petitioners

D Submissions by all the five respondents on common issues

D.1. Entire investigation is biased in favour of the domestic industry:

- a. by recommending duty on forged products not imported into India,
- b. in determining duty at a rate in a manner not revealed in the Final Finding.

c. in determining 'like article' for the exporter to compare with its normal value and for determining the domestic industry by examining the imported article.

D.2. Product under consideration shall not cover products not imported into India - Section 9(A) (1) of the Customs Tariff Act empowers the Central Government to impose AD Duty only on 'an article' being exported to India. But the investigation covers products that are not imported also, namely:

- (i) Forged FAB and Machined FAB are not 'like article' as there is wide fluctuation in their cost and they are not substitutable - Only machined FABs have been imported into India and hence AD Duty cannot be imposed on FABs not machined
- (ii). Unique models of FAB and SK are not substitutable or interchangeable with other models. This has been accepted by the Authority also. When only unique models of FAB and SK have been imported, investigation shall cover only these models imported.

D.3. Dumping margin and injury margin calculations are incorrect for the following reasons:

- (i). There have been no imports of FABs 'as forged'. Hence, no dumping margin or injury margin can be determined for the grade and so no Anti-Dumping Duty should have been recommended for this product.
- (ii). When individual dumping margins and injury margins have been determined separately for forged and machined FABs and SKs, a single weighted average rate of dumping margin and injury margin cannot be recommended. That will be against the decision of the Designated Authority in catalyst case which merged with the judgment of the Hon'ble Supreme Court [DA v. Haldor Topsoe A/S 2000 (120) E.L.T. 11 (S.C.)].

D.4. The domestic industry has any way undertaken during the public hearing to file a separate injury statement for these models alone. We request the Authority to determine injury and causal link analysis taking into account the data meant for the models imported into India based on the revised statement.

D.5. Causal link analysis is highly deficient for the following reasons:

- (i). Sales of the petitioner to Ashok Leyland increased many fold during the same period when the alleged dumped imports happened.
- (ii). Merely because domestic industry lost sales volumes of other models which resulted in deterioration of profits, return on investment and cash profits cannot be held to be a reason for causing injury.
- (iii). No explanation has been given to explain as to how an increase in imports of FAB by 1,456 MT could have led to a fall in sales by 11,892MT.
- (iv) No explanation has been given to explain as to how an increase in imports of SK by a mere 30 MT could have led to a fall in sales by 2,080 MT

(v) Other vehicle manufacturers not procuring from the petitioner, which has been the sole causal factor for the alleged injury to the domestic industry. This can in no way be attributed to the alleged dumped imports.

(vi) If at all the Authority concludes that the alleged imports have also caused injury to the domestic industry, it is prayed that the injury margin be segregated into injury caused by contraction in demand and alleged imports and AD Duty be recommended only to that portion of injury caused by dumped exports to India.

D.6. Post-POI data shall not be used for select indices to arrive at certain illogical conclusions. If at all it is used, it must be used for Post-POI second quarter also.

D.7. Return on capital employed considered for calculating NIP is unreasonable –Indian Spinners Association vs. DA (2004) 170 ELT 144 relied upon.

Rejoinder Submissions on behalf of M/s. Hubei Tri-Ring Auto Axle Co. Ltd., China PR; M/s. Hubei Tri-Ring Forging Co. Ltd., China PR; M/s Hubei Tri-Ring Motor Steering Gear Co. Ltd, China PR; M/s TATA Motors Ltd, India and M/s Ashok Leyland Ltd, India to the submissions of the domestic industry.

5. The following rejoinder submissions, in brief, have been made on behalf of these interested parties:

- **100% procurement done from China PR:** Considering the 15-19 months period involved in selection of an exporter, it has been contended that *'there is establishment of injury that dumping is causing and is likely to cause'*. However, the decision to start sourcing from a second supplier is a move to reduce dependency on one source of raw material. The procurement from the petitioner has in fact seen a tremendous increase in POI showing that the imports have not injured the petitioner. The claim of the petitioners that Ashok Leyland has planned almost 100% purchases from China PR is incorrect. It can be noted that procurement of FABs and SKs from the petitioner has increased by 113% and 226% respectively during the POI.
- **Product under investigation and like article:** The petitioner has claimed that all models of FABs and SKs manufactured by it are like products to the imported models. The same claim of the exporters in determining normal value has been rejected by the Authority stating that there are 'notable difference' between the models. Hence, the claim of the domestic industry should also be rejected.
- **Constitution of Domestic Industry:** The petitioners claim that Tata Motors has not made any claim that HVAL to be regarded as a domestic producer is incorrect. Letter filed by Tata Motors in this regard is available in the public file. The petitioner has relied upon the finding of the Authority in the case of Metallurgical Coke from China PR to substantiate its claim that production of HVAL shall be regarded as a separate market. However, the finding of the Authority is not applicable to the facts of this case. As observed in para 27 of the finding, RINL which sought to be regarded as domestic producer in that case was not producing the subject goods at all. Therefore, the entire analysis of proviso to the definition of domestic industry by the Authority becomes an '*obiter dicta*' which cannot be regarded as precedence. Reliance placed on Mohandas Issardas v. A.N. Sattannathan 2000 (125) E.L.T. 206 (Bom.) and

1292 4/12-7

Municipal Corporation of Delhi vs GurnamKaur 1989 AIR 38 (SC). Even otherwise, in Metallurgical Coke case, RINL's production was regarded as a captive consumption as their production was consumed internally within their process of production of other articles. However, in the case of Tata Motors/ HVAL, FABs and SKs produced by HVAL is consumed by Tata Motors which are two different legal entities. Hence, the facts before the Authority now completely different from the earlier case. The ruling of the CESTAT in the case of Pig Iron Manufacturers Association case is not on the point that has been now raised in this case that proviso to Rule 2(b) is not satisfied in the given facts. Hence, the legal issue raised before the Authority now is not completely new.

- Exports of FABs and SKs by a related party of petitioner in China: The petitioner has contended that it has not imported FABs or SKs. But, a related exporter of the petitioner in China PR has exported Front Axle Assemblies which are nothing but import of FABs and SKs along with other components. Therefore, the petitioner becomes ineligible to be treated as domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.
- Granting of MET to Hubei Group: The petitioner has stated that Hubei Group cannot be granted MET as there exists significant share holding by the Government. However, significant state share-holding by itself does not mean that there exists Government control. Reliance placed on the recent ruling of the Appellate Body in the case of United States - Definitive Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, WT/DS379/AB/R, 11th March, 2011 which observed as under

“the mere fact that a government is the majority shareholder of an entity does not demonstrate that the government exercises meaningful control over the conduct of that entity, much less that the government has bestowed it with governmental authority”

- The petitioner has also contended that the exporter have not provided any evidence to establish that the prices of basic inputs substantially reflect market values. But, steel, the basic raw material has always been available in the Chinese Market only at the prices at which they are available in the international market. India itself has granted MET to producers of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel inter alia from China PR and in the case of Ball Bearings from China PR who use steel as the primary raw material. Therefore, there is no question of the raw material not being available at a price not reflecting the international market price. Therefore MET to Hubei group cannot be denied.
- Concealment of data by exporters and imports: The petitioner has contended that the exporter and the importer have not fully disclosed the volume of trade between them. This contention is factually incorrect and uncalled for. The Authority has verified the export details and no variation whatsoever was noticed.
- Orders pending supplies are to be considered: The petitioner has claimed that the order placed by the importer that was pending supplies were also to be regarded as imports for the purpose of the investigation. Hubei Group and Ashok Leyland submit that there were no orders which were pending delivery after November 2009.

- Injury and causal link: The petitioner has rightly pointed out that decline in demand for the product is because of decline in production of medium and heavy commercial vehicles. However, it has contended that within the available demand, the domestic industry has lost its market share, thus establishing injury to the domestic industry. This statement of the petitioner only hides more than what it reveals. The petitioner has been supplying FABs and SKs to all the vehicle manufacturers in India including Ashok Leyland. But Ashok Leyland is the only vehicle manufacturer that has imported the subject goods. Had the imports impacted the petitioners, it is only the procurement by Ashok Leyland that should be impacted. On the contrary, sales of subject goods to Ashok Leyland has increased by 113% and 226% respectively during the POI, establishing the clear absence of any link between the imports and the alleged injury.
- Price undercutting: The petitioner has claimed that there is significant price undercutting of the selling price of the domestic industry by the imports. Considering the 113% and 226% increase in procurement of the FABs and SKs from the petitioner by Ashok Leyland, it is abundantly clear that the price undercutting has in no way impacted the petitioner.
- Economic parameters of domestic industry: The petitioner has claimed that all the economic parameters of the domestic industry have shown deterioration. However, all the negative parameters shown by the petitioner is only due to fall in demand and not due to imports. The reduced production due to fall in demand resulted in increased costs and thereby resulting in losses to the petitioner. The imports have in no way caused injury to the domestic industry.
- Threat of material injury: The petitioner has claimed that the case clearly establishes the domestic industry is threatened with material injury to dumped imports, by claiming the following parameters:
 - a. Steep increase in imports in relatively short period – There has been a steep increase in procurement from the petitioner – 113% in the case of FAB and 226% in the case of SK, all within a period of 6 months.
 - b. Ashok Leyland has shifted to 100% import from China PR – Frivolous claim in completely contrary to facts.
 - c. Ashok Leyland has a long term procurement plan from China PR – In today market scenario, holding more than one source for raw material is not unusual. This has in no way impacted the procurement from the petitioner whatsoever as procurements from the petitioner have not seen a fall.
 - d. Imports increased in a relatively short period – Repetitive claim, already addressed above.
 - e. Price undercutting is significant – This has in no way impacted the procurement from the petitioner and therefore has not impacted the petitioner. Prices for procurement of goods by user industry were mutually arrived based on cost plus reasonable profit to the applicant, so the applicant cannot claim injury.
 - f. Capacities of Hubei group are more than the domestic demand – A frivolous claim unsubstantiated with evidences. In fact the exporter is operating at more than its optimal capacity.

- g. Significant share in domestic market held by the exporters –It is only Ashok Leyland that has imported the subject goods. But the petitioner has been selling them to every other vehicle manufacture in India. With only Ashok Leyland importing the goods, how can significant market be held by the exporters! The loss of market share is only virtual situation due to contraction in demand.
- Causal Link: The specific reference of the petitioner towards Annexure 2 to the Rules and Article 3.5 of the WTO Agreement in fact strengthens the case of the exporters. These regulations cast the following requirements on the Authority that the DA shall examine any known factor other than dumping causing injury to the domestic industry and that injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Admittedly, injury to the domestic industry has been caused due to contraction in demand, competition between domestic producers and alleged dumping. Without prejudice to the submission that the imports have not caused any injury to the petitioner, if at all there is any injury to the domestic industry, only that part of injury that is caused due to dumping should be attributed to imports and duty shall be recommended only to such an extent.
- Reliance placed on EC decisions: The petitioner has relied upon a few EC decisions to show that in the case of contraction of demand, the fall in volume of sales to the domestic industry must be in proportion to the rate of fall in demand and anything over and above should be attributed to dumped imports. The petitioner has in fact increased the sales of its models that have been imported. The increase in sales to Ashok Leyland is despite the fact that the FAB and SK market as a whole had seen a fall of 21% and 25% respectively during the POI as noted by the Authority. Thus, despite a fall in the entire market, the petitioner was able to increase the sales of the models that were imported into India.

Written Submissions made by the domestic industry

6. The following written submissions, in brief, have been made on behalf of the domestic industry:
 1. The process of buying and selling in this industry requires Vendor Development which involves the following steps - establishment of capacity and capability to produce and supply, price offer, offer acceptance, Placement of purchase order and Commercial production.
 2. Chinese producers have offered materially lower prices and have taken away a very significant share of Indian market.
 3. The Chinese companies must establish that they are operating under market economy environment. What the Chinese companies claim as “cheap” may in fact, be an issue of “non market economy symptom”.
 4. The raw material in the products under consideration is steel, prices of which in China do not substantially reflect market values.
 5. The exporters have not provided any evidence to establish that prices of basic inputs substantially reflect market values.
 6. Capacities created by the producers in China PR are more than their domestic demand.
 7. FAB and SK have been considered as two dislike articles. FAA (front axle assembly) is entirely a different product.

8. TML production is entirely for captive consumption and therefore cannot be considered for the present purpose.
9. Orders pending supplies are required to be considered.
10. Within the available demand, the domestic industry has lost its market share due to dumping.

Rejoinder submissions on behalf of the domestic industry

7. The following rejoinder submissions, in brief, have been made on behalf of the domestic industry:
 1. The prices of inputs in China do not substantially reflect market values. When prices in Chinese market are low, it follows that the Chinese producers get the inputs at such artificially low prices, regardless of their relationship with the suppliers. Appropriateness of price because of relationship between the buyer & seller and appropriateness of price because of non-market economy situation are two altogether different situations.
 2. In a situation where a number of companies in the Group are involved in production and/or sale of the product under consideration, market economy status of all such companies are required to be examined before market economy treatment can be granted. Admittedly, the group as a whole has not filed questionnaire response.
 3. The key management personnel in the company are under direct supervision and control of Govt. of China. Thus, state interference cannot be ruled out.
 4. The raw material in the products under consideration is steel, prices of which in China do not substantially reflect market values. Steel forms 70-80% of the cost of production. Further, prices of coal and coke used in the production of steel do not reflect market values in China.
 5. While subsidies granted to the producers of the product under consideration are a subject matter of subsidies investigations, ad-hoc administration of subsidies, supports to the raw material producers or in turn to their input suppliers is not a subject matter of subsidies investigations.
 6. TML production is entirely for captive consumption and therefore cannot be considered for the present purpose. The captive production of TML is required to be excluded for the purpose of standing. Notwithstanding, the share of petitioner in production constitutes "a major proportion".
 7. Injury to the domestic industry is more aggravated if the information in respect of activities relating to ALL alone are considered. The Designated Authority is required to determine injury by considering all types and all buyer.
 8. The fact that imports have increased in a situation where demand has declined, at the least, establishes intensified injury to the domestic industry because of increased imports. While the industry was already facing lack of demand, the difficulties of domestic industry have been compounded by increased imports.
 9. Consumer has consumed significant volumes of the imported material in the post period of investigation. To that extent, the domestic industry lost opportunities to sell the material in the post POI even when the consumer was engaged in production.
 10. Imports have continued even after 2008-09. The imports have continued even till now, albeit with varying volumes.

1292 9/12-8

Examination by the Authority

8. The issues raised by the interested parties during the course of the public hearing as reflected in their written submissions and rejoinders submissions thereof have been examined as follows:
 - The Authority notes that the Chinese exporters' claim of MET status was duly examined by the Authority but was not accepted for the reasons recorded in paras 25-42 of the final findings and the same are being relied upon. The interested parties have also claimed that significant 'State share holding' does not translate into 'State interference' in a Company. However, it is noted that the interested parties did not discharge the onus that lies upon it to prove that regardless of the significant State holding in its company, it is entitled for market economy treatment. The Authority further notes that it has not opined whether the subsidies are being provided by Chinese Government; rather the Authority has based its findings in terms of AD Rules and regulations on the subject, which, *inter alia*, provide that there shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3). It is noted that Chinese exporters failed to rebut the presumption in the instant matter.
 - It has also been contented that the Authority has ignored the provisions of Section 9A (6A). The interpretation given to Section 9A (6A) by the Chinese exporters cannot be accepted as such a contention is not supported by the basic rules of Interpretation of statutes. Section 9A (6A) is a general provision which merely states that the margin of dumping in relation to an article exported by an exporter or producer shall be determined on the basis of records maintained by such exporter or producer and on the basis of information available in the case of non-cooperating exporter or producer. Paragraph 7 & 8 of Annexure I of the AD rules, on the other hand, deals specifically with calculation of normal value and export price in case of a "Non-market economy". It is an accepted rule of interpretation that a special provision overrides a general one. Hence, the Authority considers that it has correctly calculated the normal value and export price in case of a non-market economy as stipulated by the AD rules.
 - As regards the issue regarding confidentiality, as the Normal value was constructed, *inter alia*, based on confidential information of the domestic industry, the same could not have been disclosed. The claims of confidentiality made by the domestic industry were duly examined by the Authority and upon its satisfaction were accepted in terms of para 7 of the AD Rules.
 - As regards the contention that M/s Bharat Forge Limited does not constitute domestic industry as its total share in production is a mere 28.17% as against the share of TATA Motors amounting to 64.23%; the Authority notes that the issue was duly examined while issuing the findings in the instant matter. The Authority relies upon Para 17 of its Final findings on the subject wherein its has been noted that (a)

production of each of the subject goods by the applicant constitutes a major proportion of the Indian production (b) Production of each of the subject goods by the applicant along with that of the supporters constitute more than 50% of the Indian production (c) that the application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the AD Rules. Thus, M/s Bharat Forge Limited constitutes domestic industry for each of the products under consideration within the meaning of the Rule 2(b) read along with Rule 2(d) of the AD Rules.

- As regards the contention that models imported by Ashok Leyland are unique articles which cannot be used anyone else and that the imports by Ashok Leyland did not lead to a decline in their purchases from the applicant industry and therefore the imports have not injured the applicant industry; the Authority notes that contention is devoid of any merit as the domestic industry lost orders of the subject goods, ostensibly due to the cheaper prices of the subject goods offered from the subject country. It has not been a claim of M/s Ashok Leyland that the domestic industry is incapable of supplying the goods in question to them.
- As regards the contention that product under consideration should not cover products not imported into India and that the dumping margin and injury margin calculations are incorrect; the Authority notes that the contention is misleading. It may be pertinent to point out herein that the AD investigation was conducted in respect of PUCs viz. 'front axle beam and steering knuckles meant for heavy and medium commercial vehicles' and as a matter of fact it was found that the subject goods were being dumped and consequently causing injury to the domestic industry. Therefore, the Authority recommended duty on the PUCs in terms of the relevant rules and regulations on the subject. It is incorrect to state that the investigation is restricted to a particular type of the PUC that has been incidentally dumped during the POI. If such an argument is to be accepted, it will lead to circumvention of the AD measures that has been put in place and would negate the entire exercise that has been undertaken to redress the injury caused to the domestic industry due to the dumping of the products under consideration.
- As regards the Causal link analysis; the Authority notes that it has analysed the impact of dumping on the domestic industry by considering market share of various parties in the demand of the products in the country. It was then observed by the Authority the market share of domestic industry has significantly declined in the period of investigation. The data furnished by the domestic industry showed further decline in its market share in period October-December 2008 (post POI). It was noted in Para 95 of the Final findings that within the available demand the domestic industry has lost its market share. Accordingly it was concluded by the Authority that the domestic industry was already facing problem of declining demand, but the same was compounded by the dumped imports.
- The contention that the volume of import made during the year 2007-08 was meager is devoid of merits and not based on the facts. The Authority has examined the volume effect in paras 64 to 72 of the final findings, which are being relied upon.

- As regards threat of material injury, it is noted that in terms of Para vii of the Annexure II of the AD Rules, for the purposes of determination of a threat of material injury, the Authority is obliged to examine the factors stipulated therein which, *inter alia*, include the rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets and also whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on the domestic prices, and would likely increase demand for further imports. The data as available on record, which is reflected in Para 94 of the Final Findings clearly showed a steep increase in imports in a relatively short period of time, which was also evident from the relative market share of imports of the subject goods. Moreover, it was noted that the capacities created by the producers in China PR were more than their domestic demand. Therefore, a likelihood of increased volume of dumped imports flowing into the country from China PR was seen to be clearly established.
- As regards the contention that there has been an incorrect determination of the NIP is devoid of merits as the Authority has computed the Non-Injurious Price as per its consistent practice being followed over a period of time.
- The Authority notes that injury analysis has been done with due application of mind by the Authority as required under Rule 11 read with Annexure II of the Anti-Dumping Rules, 1995.

Comments on disclosure statement by interested parties

9. The Following comments, in brief, have been made on behalf of M/s. Hubei Tri-Ring Auto Axle Co. Ltd.; M/s. Hubei Tri-Ring Forging Co. Ltd.; M/s Hubei Tri-Ring Motor Steering Gear Co. Ltd; M/s TATA Motors Ltd, India and M/s Ashok Leyland Ltd, India:

- A very short time has been given to respond to the Disclosure statement.
- It has been contended that the following issues raised by them have not been addressed:
 - It has been contended that the petitioner gave an undertaking during the public hearing to provide separate injury statement for the two models of FAB and three models of SKs that were imported into India. However, no such injury information is seen in the disclosure statement.
 - it has been contended that there are 2 different types of subject goods, i.e. machined and forged, which differ significantly in terms of their costs as well as weight and therefore separate dumping and injury margin as well as separate rate of AD Duty should be determined for them. Reference has been made to Hon'ble Supreme Court in Designated Authority v. Haldor Topsoe the decision in the Andhra Petrochemicals Ltd v. DA , it has been contended that models not imported into India should not be liable to AD Duty.
 - Referring to the decisions in Indian Spinners Association vs. Designated Authority and Bridgestone India Private Limited v. Designated Authority, it

has been requested not to grant an exorbitant return on 22%. To the domestic industry while computing the NIP.

Market Economy Treatment

- It has been contended that all the directors are elected by the shareholders and there are around 43,000 shareholders. The huge number of shareholders and the fact that no raw material required for the production of subject goods are not purchased from any company with government control show that the directors are not influenced by the Government. The major raw material for the subject goods is steel. Indian Authority has in the past accepted the prices of Chinese steel to be at par with international prices and therefore there is no specific infirmity in not substantiating the accepted fact.

Determination of normal value as per books of accounts

- Referring to Section 9A(6A) of the Customs Tariff Act, it has been contended that it is a settled principle of law that the provisions of an Act will override the provisions of the Rules made thereunder. The Customs Tariff Act, 1975 is a substantive statute and the Rule is a delegated legislation and hence in the case of conflict between the two, the substantive statute will prevail. It has therefore been contended that normal value should not be constructed for the exporter and the normal value be determined as per the books of accounts maintained by the exporter

Disclosure of normal value

- It has been contended that how can international prices of a product be kept confidential.

Constituents of domestic industry

- It has been contended that the applicability of first proviso to Rule 2(b) has not been discussed. Reference has been made to the WTO Panel report in the case of US: Cotton Yarn [DS 192R].
- It has been contended that the principle that an order that does not consider the legal provisions and the arguments raised by the interested party is a non-speaking order which only results in avoidable litigation. A mere 28% share-holding producer cannot be regarded as 'domestic industry' within the meaning of the statute. Reference has been made to 'Anti-Dumping Duty on imports of Seamless Tubes and Pipes from China [Termination Notification No. F.No. 14/55/2009-DGAD dated 18th November, 2010.

Causal Link

- It has been contended that the domestic industry has not lost any orders due to the imports made into India. Next, the loss of orders of any other vehicle manufacturer cannot be attributed to the subject imports because none of the other vehicle

1292 4712-9

manufactures have imported the subject goods. Therefore, the subject imports have not caused any injury to the domestic industry.

Rate of duty

- The product under consideration can be either 'forged' or 'machined'. The cost of production and export price for these two types are different. When selling prices of tow grades are different, it has been contended that that a single rate of AD Duty cannot be imposed.

Recurrence of dumping

- As rightly pointed out by the Authority, threat of injury has to be determined as per Para (vii) of Annexure II to AD Rules. With regard to the conclusions arrived at by the Authority regarding recurrence of injury, we request the Authority to disclose the following information and the sources from which they were obtained: capacity in China PR is higher than the demand: size of Chinese Market for the subject goods: capacity in China PR and the source of the data and its authenticity have not been examined or disclosed. When the co-operating exporter manufacturing Steering Knuckles was operating at 92% capacity utilization during the period of investigation and 94% capacity utilization during the immediately preceding year, the Authority could not have concluded that there is freely disposable capacity to cause injury to the domestic industry.

10. The Following comments, in brief, have been made on behalf of the domestic industry:

- Domestic industry has reiterated its submissions with regard to various issues concerning investigations and has further supplemented its views on the submissions made by opposing interested parties.
- It has been contended that under the Rules, the Authority is required to consider (a) whether there has been increase in imports in absolute terms or in relation to production & consumption; and (b) whether the imports of the product under consideration are causing price undercutting, or whether the impact of such dumped imports was to depress or suppress the prices. If so, the Authority is required to consider consequent impact of the dumped imports in terms of a number of economic parameters. Clearly, consequent impact of the dumped imports on the domestic industry has been adverse and significant.
- The domestic industry has claimed that sales of domestic industry to Ashok Leyland declined significantly and the same shows injury caused to the domestic industry.
- Injury to the domestic industry cannot be determined separately in respect of individual models. Injury is required to be determined in respect of like article. Existence of a number of different forms of the product only implies that the Authority shall consider the same for dumping margin and injury margin and undertake model by model analysis. The injury analysis in any case is required to be carried out for the like article. Even the eventual dumping margin and injury margin

are required to be determined for the product as a whole. Existence of significant difference in the prices of different types/models of the product under consideration does not imply that they are dislike article. Only for the purpose of dumping margin and injury margin, the authority is required to consider model by model comparison.

- Sourcing of low-priced imports led M/s Ashok Leyland to source its increased requirement from China PR.
- Standing of the petitioner is required to be determined with reference to "Indian production" and not on the basis of "production for domestic market". Production of HVAL is required to be ignored even if it is considered that it is not a captive consumption and Tata Motors and HVAL are two different but related entities. Rule 2(b) proviso deals with the situation where the market is divided in two or more competitive markets.
- Front Axle Assembly is different from Front Axle Beam or Steering Knuckle. Authority has not considered Front Axle Beam or Steering Knuckle as one like article. Authority has considered these as distinctly dislike article being investigated through a combined investigation. Front Axle Beam or Steering Knuckle cannot be considered as the same article as Front Axle Assembly.
- The onus to establish market economy is on the responding company in a situation where more than one company is involved in production or sale. The Authority should accept questionnaire response only if group as a whole has filed the response. Since other group companies involved in production and sale have not filed questionnaire response, the Authority, in any case, should not accept the claim for market economy status. In a situation where the shareholding is by the State, the exporter has to establish absence of interference or control not only in the past action but also no possibility in future. No information has been given in this regard by the exporter. The exporter has not established that prices of inputs substantially reflected the market values.
- In a situation where demand for the product declined and market share of domestic industry declined and that of imports increased clearly establishes that the injury to the domestic industry is due to dumped imports. Under the rules, adverse consequent impact of dumped imports can be visible in any of the economic parameters listed under the law. Increase in imports despite recession itself and increase in market share of the domestic industry is sufficient to establish that the dumped imports caused injury to the domestic industry.

Examination by the Authority

11. The issues raised by the interested parties in response to the Disclosure statement have been examined as follows:

- The Authority notes that due to time constraints, a short time was provided to the interested parties to respond to the Disclosure statement. However, a number of opportunities have been provided to the interested parties to file their submissions from time to time during the course of this investigation. The interested parties have

1292 9/12-10

also not raised any significant new point and apparently no prejudice has been caused to them by providing them a short period to respond to the Disclosure statement.

- The Authority notes that the petitioner has given no undertaking to provide separate injury statement for the two models of FAB and three models of SKs that were imported into India.
- It is further noted that that there are 2 different types of subject goods, viz Front Axle Beam and Steering Knuckles and not as machined and forged as has been contended by the respondents. While the Authority may carry out its analysis of dumping margin and injury margin on PCN basis in a given case but the investigation is conducted to determine whether the product under consideration has been dumped and causing 'injury' to the domestic industry or not. Thus, contentions made by the respondents are devoid of any merit.
- As regards the MET claim, the Authority reiterates that the Chinese exporters' claim of MET status was duly examined by the Authority but was not accepted for the reasons recorded in paras 25-42 of the final findings and the same are being relied upon. The interested parties have also claimed that significant 'State share holding' does not translate into 'State interference' in a Company. However, it is noted that the interested parties did not discharge the onus that lies upon it to prove that regardless of the significant State holding in its company, it is entitled for market economy treatment. The Authority further notes that it has not opined whether the subsidies are being provided by Chinese Government; rather the Authority has based its findings in terms of AD Rules and regulations on the subject, which, inter alia, provide that there shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3). It is noted that Chinese exporters failed to rebut the presumption in the instant matter.
- As regards Section 9A (6A), the Authority reiterates that the interpretation given to Section 9A (6A) by the Chinese exporters cannot be accepted as such a contention is not supported by the basic rules of Interpretation of statutes. Section 9A (6A) is a general provision which merely states that the margin of dumping in relation to an article exported by an exporter or producer shall be determined on the basis of records maintained by such exporter or producer and on the basis of information available in the case of non-cooperating exporter or producer. Paragraph 7 & 8 of Annexure I of the AD rules, on the other hand, deals specifically with calculation of normal value and export price in case of a "Non-market economy". Hence, the Authority considers that it has correctly calculated the normal value and export price in case of a non-market economy as stipulated by the AD rules.

- As regards the issue regarding confidentiality; the Authority reiterates its view that as the Normal value was constructed, *inter alia*, based on confidential information of the domestic industry, the same could not have been disclosed. The claims of confidentiality made by the domestic industry were duly examined by the Authority and upon its satisfaction were accepted in terms of para 7 of the AD Rules.
- As regards the constituents of domestic industry; the Authority notes that on the basis of facts available on record and in terms of the AD Rules, M/s Bharat Forge Limited constitutes domestic industry for each of the products under consideration within the meaning of the Rule 2(b) read along with Rule 2(d) of the AD Rules.
- As regards the injury and Causal link analysis; the Authority notes that it has analysed the impact of dumping on the domestic industry by considering market share of various parties in the demand of the products in the country; it is seen the market share of domestic industry has significantly declined in the period of investigation. The data furnished by the domestic industry showed further decline in its market share in period October-December 2008 (post POI). It was noted in Para 95 of the Final findings that within the available demand the domestic industry has lost its market share. Accordingly it was concluded by the Authority that the domestic industry was already facing problem of declining demand, but the same was compounded by the dumped imports. The analysis as reflected in the Final findings dated 5th March 2010 is being relied upon.
- As regards threat of material injury, it is noted that in terms of Para vii of the Annexure II of the AD Rules, for the purposes of determination of a threat of material injury, the Authority is obliged to examine the factors stipulated therein which, *inter alia*, include the rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets and also whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on the domestic prices, and would likely increase demand for further imports. The facts available on record showed a steep increase in imports in a relatively short period of time, which was also evident from the relative market share of imports of the subject goods. Moreover, it was noted that the capacities created by the producers in China PR were more than their domestic demand. Therefore, a likelihood of increased volume of dumped imports flowing into the country from China PR was seen to be clearly established. It is not imperative that all the factors as reflected in para vii of the Annexure II of the AD Rules must necessarily show an adverse impact.
- As regards the contention that there has been an incorrect determination of the NIP; the Authority reiterates that the contention is devoid of merits and that the Authority has computed the Non-Injurious Price as per its consistent practice.

12. After careful examination of the submissions made by interested parties on the subject and considering the legal provisions and facts of the case, the Authority notes that facts on record do not justify any modification to the final findings dated 5th March 2010.

Conclusion:

13. Having given opportunity in terms of the orders of Hon'ble CESTAT to all the parties to make oral as well as written submissions, the Authority has examined the same in the paras given above. After having examined the submissions of all the parties, the Authority confirms the conclusions arrived at earlier and indicated in the final findings dated 5th March 2010.
14. The Authority therefore confirms its earlier recommendation of imposition of the definitive anti-dumping duties on the subject goods from the date of notification issued in this regard by the Central Government on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country. The Authority further concludes that no change to the relevant Government of India, Ministry of Finance's Notification is warranted.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority